दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड बनाम विद्युत लोकपाल,हरियाणा,पंचकुला और अन्य (कँवलजित सिंह आहलुवलिया जे.)

माननीय न्यायमूर्ति कँवलजित सिंह आहलुवलिया

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,हिसार

-याचिकाकर्ता

बनाम

विद्युत लोकपाल, हरियाणा, पंचकुला और अन्य

-उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. 2008 का क्रमांक 19668

25 नवंबर 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) और (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004- विनियमन 2(h), (j) और (k) और 22- निगम बिजली लोकपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है जिसमें लाइसेंसधारी निगम के उपभोक्ताओं को उनके द्वारा की गई खपत सुरक्षा और मीटर सुरक्षा जमा पर 6% ब्याज पाने का अधिकार दिया गया है- क्या उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और बिजली लोकपाल के पास धारा 47(4) के विषय से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र या कानून का कोई अधिकार है - निर्धारित किया गया कि बिजली लोकपाल आदेश पारित करने के अपने अधिकार में था क्योंकि यह आदेश को प्रभावी करने के लिए था - उचित आयोग द्वारा दर का निर्धारण- लोकपाल का आदेश सिर्फ़ उसे प्रभाव में लाने के लिए-लोकपाल केवल ब्याज की दर निर्धारित करने के बाद अप्रैल, 2003 से उपभोक्ताओं को ब्याज का हकदार मानता है।

यह निर्धारित किया गया कि विद्युत लोकपाल केवल उपयुक्त आयोग (वर्तमान मामले में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग) द्वारा दिए गए सामान्य आदेशों या निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहा था।। एचईआरसी ने अपने विवेक से 2004 के विनियम 23 को हटा दिया था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा इस भाग को भी चुनौती नहीं दी गई। अपील का अधिकार जो निहित था, छोड़ दिया गया। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है कि उपभोक्ता

शिकायत निवारण फोरम और बिजली लोकपाल के पास याचिकाकर्ता द्वारा तैयार अधिनियम की धारा 47(4) के विषय से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र या कानून का कोई अधिकार नहीं है और यह निर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्युत लोकपाल आदेश पारित करने के अपने अधिकार में था क्योंकि उसे आदेश को प्रभावी करना था।

(पैरा 34)

इसके अलावा, प्रश्न संख्या 2 कि क्या सीजीआरएफ और/या विद्युत लोकपाल केवल विनियम 2(m) और 2(n)) के साथ पढ़े गए विनियम 2(h) के तहत निर्दिष्ट मामलों से निपटते हैं। उत्तर यह है कि विद्युत लोकपाल इस मामले से निपट सकता है क्योंकि आयोग द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान न करना अनुचित व्यवहार है। अन्यथा भी, उपभोक्ता होने के नाते प्रतिवादी नंबर 3, 2004 विनियमों के विनियम 2 (h) के तहत शिकायत दर्ज करने का हकदार था। विनियम 2(k) उपभोक्ता विवाद को परिभाषित करता है। उपभोक्ता विवाद की परिभाषा बहुत व्यापक है, ब्याज का भुगतान न करना या एच.ई .आर.सी द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान करना सुरक्षित रूप से उपभोक्ता विवाद कहा जा सकता है। इसलिए विद्युत लोकपाल विवादित आदेश पारित करने के अपने अधिकार क्षेत्र में था।

(पैरा 36)

इसके अलावा, यह माना गया कि दर उपयुक्त आयोग, एचईआरसी, द्वारा निर्धारित की गई थी, लोकपाल केवल उसी को प्रभावी कर रहा था। अत: उन्होंने, ब्याज दर का निर्धारण के बाद, उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2003 से ब्याज का हकदार माना था। 2003 अधिनियम 10 दिसंबर, 2003 को हरियाणा राज्य में लागू किया गया था, इसलिए, 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत, उपभोक्ता ब्याज के भुगतान के हकदार थे। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में उपभोक्ता उस तारीख से ब्याज के हकदार होंगे जब 2003 अधिनियम हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया था यानी 10 दिसंबर, 2003 से, न कि अप्रैल, 2003 से। प्रश्न संख्या 3 कि क्या 20 दिसंबर, 2007 के विवादित आदेश को पारित करते समय विद्युत लोकपाल की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून की नजर में यह गैर-स्थायी है, का उत्तर यह है कि लोकपाल आदेश(अनुलग्नक पी 8) को प्रभावी कर रहा था क्योंकि उपभोक्ता जिस दिन से ब्याज के हकदार बन गए उसी दिन से ब्याज की माँग कर रहे थे और उन्होंने रिट याचिका दायर करके और बाद में एचईआरसी से संपर्क करके अपने दावों को आगे बढ़ाया था। लेकिन वैधानिक अधिकार उन्हें 10 दिसंबर, 2003 से मिला। इसलिए, उस तारीख से उपभोक्ता ब्याज के हकदार होंगे।

(पैरा 37)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, विकास सूरी।

उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के लिए कोई नहीं।

जी.के.चावला, प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता

कँवलजित सिंह आहलुवलिया जे.(मौखिक)

(1) पार्टियों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि सिविल रिट याचिका संख्या 19668, 19670, 19671, 19672 और 19673 जिसका शीर्षक "**दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार बनाम बिजली लोकपाल, हरियाणा, पंचकुला और अन्य"** है, का निपटारा किया जा सकता है। तथ्यों, कानून और उठाए गए विवाद के आधार पर सामान्य निर्णय से, ये सभी रिट याचिकाएँ प्रकृति में समान हैं।

(2) संदर्भ की सुविधा के लिए, 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 19668 से तथ्य एकत्र किए गए हैं, जिसका शीर्षक "दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार बनाम बिजली लोकपाल, हरियाणा, पंचकुला और अन्य" है।

(3) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित) ने 20 दिसंबर, 2007 के विवादित आदेश (अनुलग्नक पी9) को रद्द करने की मांग के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत बिजली लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लाइसेंसधारी निगम के उपभोक्ता अपने द्वारा की गई उपभोग सुरक्षा और मीटर सुरक्षा जमा पर 6% ब्याज पाने के हकदार हैं।

(4) रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए हैं:-

(1) क्या अधिनियम की धारा 47(4) के विषय से निपटने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षिप्त में "सीजीआरएफ") और विद्युत लोकपाल के पास अधिकार क्षेत्र या कानून का कोई अधिकार है?

(2) क्या सीजीआरएफ और/या विद्युत लोकपाल केवल विनियम 2(m) और 2(n) के साथ पठित विनियम 2(ह) के तहत निर्दिष्ट मामलों से निपटते हैं?

(3) क्या विद्युत लोकपाल द्वारा 20 दिसंबर,2007 को विवादित आदेश(अनुलग्नक पी9) पारित करते समय, की गयी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून की नजर में गैर-स्थायी है?

(4) क्या 2005 के विनियम में निर्दिष्ट ब्याज दर देय हैं और उस संबंध में एचईआरसी के निर्देश अधिनियम की धारा 47 के आदेश का पर्याप्त अनुपालन करते हैं?

(5) इस रिट याचिका की बहस के दौरान इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न भी उठे हैं, जिन्हें सूत्रीकरण के बाद क्रम संख्या दी गई है:-

(5) क्या लोकपाल हरियाणा राज्य नियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों से बंधा हुआ है और उसी की व्याख्या में बैंक दर निर्धारित कर सकता है या नहीं?

(6) भारतीय रिजर्व बैंक की दर क्या है या यह प्रचलित बचत बैंक खाता दर से भिन्न है?

(6) रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया कि वह निगम का उपभोक्ता है, याचिकाकर्ता एक बिजली वितरक है।

(7) विद्युत अधिनियम, 2003 (बाद में इसे "2003 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 82 राज्य आयोग के गठन की गणना करती है, जिसे विद्युत नियामक आयोग कहा जा सकता है और वर्तमान मामले में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद इसे "एचईआरसी" कहा जाएगा) है।"विद्युत अधिनियम, 2003" के परिचय में निर्दिष्ट कारण व उद्देश्य का वर्णन करते हुए, इस प्रकार बताया गया:---

"1.3 समय के साथ, हालांकि, विभिन्न कारकों के कारण राज्य बिजली बोर्ड का प्रदर्शन काफी हद तक खराब हो गया है। उदाहरण के लिए, हालांकि टैरिफ तय करने की शक्ति राज्य बिजली बोर्डों के पास है, लेकिन वे आम तौर पर पेशेवर और स्वतंत्र तरीके से टैरिफ पर निर्णय लेने में असमर्थ रहे हैं और व्यवहार में टैरिफ निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। क्रॉस-सब्सिडी अस्थिर स्तर पर पहुंच गई है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए और टैरिफ के निर्धारण से सरकार को दूर रखने के लिए, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था।इसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग बनाया और इसमें एक सक्षम प्रावधान है जिसके माध्यम से राज्य सरकारें एक राज्य विद्युत नियामक आयोग बना सकती हैं। 16 राज्यों ने अब तक केंद्रीय अधिनियम के तहत या अपने स्वयं के सुधार अधिनियमों के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिसूचित/बनाया है। "

(8) इस प्रकार, एचईआरसी को न केवल टैरिफ निर्धारित करना है बल्कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करनी है।

(9) 2003 अधिनियम की धारा 85 राज्य आयोग के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान करती है।

(10) इस याचिका में, निर्णय की सुविधा के लिए, न्यायालय का संबंध धारा 86 से है जो राज्य आयोग के कार्यों को प्रदान करता है। संदर्भ की सुविधा के लिए, 2003 अधिनियम की धारा 86 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:--

धारा 86. (राज्य आयोग के कार्य):-

(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

A. राज्य के भीतर, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करें।

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की एक श्रेणी के लिए खुली पहुंच की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल व्हीलिंग शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा;

B. वितरण लाइसेंसधारियों की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह कीमत भी शामिल है जिस पर राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के समझौतों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों से या अन्य स्रोतों से बिजली खरीदी जाएगी;

C. बिजली के अंतर-राज्य पारेषण और व्हीलिंग की सुविधा प्रदान करना;

D. राज्य के भीतर अपने संचालन के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों, वितरण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

E. ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी और किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का एक निर्धारित प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना;

F. लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय देना और मध्यस्थता के लिए विवाद को संदर्भित करना;

G. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क लगाना;

H. धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (h) के तहत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड निर्दिष्ट करें;

I. गुणवत्ता, लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्दिष्ट या लागू करना,;

J. बिजली के अंतर-राज्य व्यापार में व्यापार मार्जिन तय करना,यदि आवश्यक समझा जाए; और

K. ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे जा सकते हैं।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देगा, अर्थात्: -

(i) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना;

(ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

(iii) राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण;

(iv) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

(3) राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(4) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना एवं टैरिफ नीति धारा 3 के द्वारा निर्देशित होगा।

(11) 2003 अधिनियम की धारा 86(1)(ए) के तहत, बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करने की शक्तियां राज्य आयोग में निहित हैं, इसलिए, एक वितरण कंपनी केवल उन टैरिफ को चार्ज कर सकती है जो राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित हैं। 2003 अधिनियम की धारा 42 पर एक नजर डालने के लिए कहता है। 2003 अधिनियम की धारा 42, वितरण लाइसेंसधारियों के कृतव्य और खुली पहुंच को परिभाषित करती है। इस निर्णय के प्रयोजन के लिए केवल 2003 अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 5. 6, 7 और 8 का संदर्भ देना आवश्यक है। जो इस प्रकार है:

"**धारा 42. (वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं खुली पहुंच के कर्तव्य) :-**

(1) से (4) XXX XXX

(5) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, लाइसेंस देने की नियत तारीख या लाइसेन्स मिलने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फ़ोरम स्थापित करें।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायतों का निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल नामक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है।

(7) लोकपाल, उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से करेगा जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) उप-धारा (5), (6) और (7) के प्रावधान उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उपभोक्ता को उन उप-धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा प्राप्त हो सकता है।"

(12) एचआरईसी ने उपभोक्ताओं और उनकी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लाइसेंसधारी के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए, लोकपाल नामक स्वतंत्र अंपायर की शुरुआत की और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (दिशानिर्देश) के रूप में जाने जाने वाले नियम और (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004 (संक्षिप्त में "2004 विनियमन") अधिसूचित किये। 2004 विनियमन का विनियमन 2(h) उन मुद्दों को नोटिस करता है जिन्हें शिकायत का विषय बनाया जा सकता है। 2004 विनियमन का विनियमन 2(h) इस प्रकार है: -

"2. परिभाषा

(a)से (g) XXX XXX XXX XXX XX

(h) "शिकायत" का अर्थ शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में की गई कोई भी शिकायत है जैसे:--

(i) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई बिजली सेवा में कोई दोष या कमी है;

(ii) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली सेवाएं प्रदान करने में अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अपनाई गई है;

(iii) वितरण लाइसेंसधारी ने बिजली और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर वसूल की है;

(iv) वितरण लाइसेंसधारी ने कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराने में आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक व्यय वसूल किया है;

(v) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई बिजली सेवाएँ, सार्वजनिक जीवन के लिए असुरक्षित या खतरनाक हैं और लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हैं"

(13) 2004 के विनियम 2(j) और (k) विनियम उपभोक्ता और उपभोक्ता विवादों को परिभाषित करते हैं। इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:--

"2. परिभाषा

(a) से (i) XXX XXX

(j) "**उपभोक्ता**" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे, किसी वितरण लाइसेंसधारी या सरकार या लागू कानूनी ढांचे या किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,अपने उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर कुछ समय के लिए बिजली लेने के उद्धेश्य से वितरण लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति,जैसा भी मामला हो,के कार्यों से जुड़ा हुआ है।

(k) "**उपभोक्ता विवाद**" का अर्थ एक ऐसा विवाद है जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायत में निहित आरोप से इनकार करता है या उस पर विवाद करता है;"

(14) 2004 विनियमन के विनियम 2(m) और (n) विनियमन दोष और कमी को परिभाषित करते हैं।

(15) वर्तमान मामले में, क्या वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा उपभोक्ता विवाद, दोष या कमी है, यह एक सहायक मुद्दा है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार करना ज़रूरी है।

(16) 2004 विनियमन के विनियम 8, 9 और 10 सीजीआरएफ द्वारा शिकायत के निर्णय की प्रक्रिया बताते हैं। विनियम यह भी प्रदान करते हैं कि शिकायत पर लिया गया निर्णय 2004 विनियमन के विनियम 12 के तहत विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील योग्य है। अपील का अधिकार केवल उपभोक्ता को ही है।

(17) 2004 विनियमन का विनियम 19, विद्युत लोकपाल द्वारा शिकायत को अस्वीकार करने के तरीके का वर्णन करता है। इस न्यायालय को इससे कोई सरोकार नहीं है।

(18) 2004 विनियमन के विनियम 21 में समझौते द्वारा शिकायत के निपटान का उल्लेख है। वर्तमान मामले में, चूँकि कोई समझौता नहीं हुआ था, इस भाग को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(19) 2004 विनियमन का विनियम 22 मामले की सुनवाई और पुरस्कार को परिभाषित करता है। इसे इस प्रकार पढ़ें:--

"**22. मामले की सुनवाई और फैसला**

(1) जहां शिकायत का निपटारा विनियम 21 के तहत समझौते से नहीं होता है, विद्युत लोकपाल मामले की सुनवाई का तरीका, स्थान, तारीख और समय निर्धारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) विद्युत लोकपाल पक्षों की दलीलें सुन सकता है और पक्षों को मामले में लिखित प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

(3) विद्युत लोकपाल अपने निष्कर्षों और अवॉर्ड के कारणों को बताते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

(4) विद्युत लोकपाल शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक अवॉर्ड पारित करेगा और 7 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता, वितरण लाइसेंसधारी और एचईआरसी को अवॉर्ड की एक प्रति भेजेगा। वितरण लाइसेंसधारी/शिकायतकर्ता को अवॉर्ड के कार्यान्वयन के 7 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल को इसके अनुपालन के बारे में सूचित करना होगा।

(20) 2004 विनियमन के विनियम 23 ने आयोग को एक अपील प्रदान की। 16 अक्टूबर, 2006 को एचईआरसी द्वारा जारी संशोधन की अधिसूचना के माध्यम से यह भाग हटा दिया गया है जिसे अनुबंध पी2 के रूप में संलग्न किया गया है।

(21) प्रावधानों पर व्यापक रूप से ध्यान देने के बाद, इस मामले के निर्णय के लिए आवश्यक अन्य प्रावधानों के संदर्भ में, रिट याचिकाओं में उठाए गए विवाद का निर्धारण करने के लिए तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

(22) प्रतिवादी संख्या 3, उपभोक्ता, ने 2003 अधिनियम की धारा 47(1) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के पास सुरक्षा जमा कर दी थी। 2003 अधिनियम की धारा 47(1) कहती है:-

"**धारा 47. (सिक्यरिटी की आवश्यकता की शक्ति)**:-

(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक वितरण लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को, जिसे धारा 43 के अनुसरण में बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है, उसे उचित सिक्यरिटी देने की आवश्यकता हो सकती है,जैसा कि उसे देय सभी धनराशि के भुगतान के लिए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:-

(a) ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की गई बिजली के संबंध में; या

(b) जहां किसी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर प्रदान किया जाना है, ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर के प्रावधान के संबंध में, और यदि वह व्यक्ति ऐसी सिक्यरिटी देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी यदि वह उचित समझता है, तो उस अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति देने या लाइन या संयंत्र या मीटर प्रदान करने से इनकार कर देगा, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।"

(23) उपभोक्ता एचईआरसी द्वारा निर्धारित बैंक दर के बराबर या उससे अधिक दर पर प्रदान की गई सुरक्षा पर ब्याज का हकदार है। 2003 अधिनियम की धारा 47(4) इस प्रकार है—-

"**धारा 47 (सिक्यरिटी की आवश्यकता की शक्ति)**:-

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) वितरण लाइसेंसधारी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सिक्यरिटी पर बैंक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उस व्यक्ति,जिसने सिक्यरिटी प्रदान की है ,के अनुरोध पर ऐसी सिक्यरिटी वापस कर देगा।"

(24) 2003 अधिनियम की धारा 43, 46 और 47 के साथ पठित धारा 181 की उपधारा 2(t) के तहत एचईआरसी को नियम बनाने का अधिकार है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचईआरसी ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (अनुरोध पर बिजली आपूर्ति करने का कर्तव्य, आपूर्ति प्रदान करने में किए गए व्यय की वसूली करने की शक्ति और सिक्यरिटी प्राप्त करने की शक्ति) विनियमन, 2005 (इसके बाद इसे "2005 विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नामक विनियम बनाए। "2005 विनियम" का विनियम 5.7 इस प्रकार है:--

"**5.7 उपभोग सिक्यरिटी और मीटर सिक्यरिटी पर ब्याज**

लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा जमा की गई उपभोग सिक्यरिटी और मीटर सिक्यरिटी पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिसूचित बचत बैंक दर या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित उच्च दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। उपभोक्ता के खाते में जमा होने वाला ब्याज प्रत्येक वर्ष के अप्रैल या मई के ऊर्जा बिलों में या अंतिम बिल में समायोजित किया जाएगा यदि उपभोक्ता द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी विच्छेदन की मांग की जाती है।

(25) मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, फ़रीदाबाद ने इस प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत लाइसेंसधारी को ससिक्यरिटी पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए और 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 2847 को प्राथमिकता दी, जिसे पहले इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और उक्त रिट याचिका का निपटारा 24 फरवरी, 2006 को किया व निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:---

"अनुलग्नक पी 6 से यह स्पष्ट है कि मामला अभी भी उत्तरदाताओं के विचाराधीन है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मामले में उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तदनुसार निपटान किया गया।"

(26) इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, 27 जुलाई, 2006 को एचईआरसी ने आदेश (अनुलग्नक पी8)पारित किया। आदेश को उसकी संपूर्णता में पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

"विषय: उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई उपभोग सिक्यरिटी और मीटर सिक्यरिटी पर ब्याज।

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फ़रीदाबाद, -एमडी/डीएचबीवीएनएल और अन्य को संबोधित पत्र संख्या एमएएफ/23 दिनांक 17 मई, 2006 के माध्यम से, उपभोक्ता सिक्यरिटी पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर के संबंध में मामला आयोग के ध्यान में लाया गया है। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फ़रीदाबाद ने इस संबंध में

एसोसिएशन द्वारा दायर 2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2847 का भी उल्लेख किया है, हालांकि, उक्त सीडब्ल्यूपी के संबंध में आयोग को पहले कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(4) के प्रावधानों और आयोग के विनियमन संख्या एचईआरसी/ 12/2005 की धारा 5.7 के मद्देनजर उद्धृत विषय पर विचार किया है। मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी उपभोक्ता प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैंक दर पर तत्काल प्रभाव से किया जाए। जैसा कि उपरोक्त विनियमन में पहले से ही प्रदान किया गया है, उपभोक्ताओं के क्रेडिट पर अर्जित ब्याज को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल या मई के ऊर्जा बिलों में या अंतिम बिल में समायोजित किया जाएगा यदि उपभोक्ता द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी विच्छेदन की मांग की जाती है।"

(27) प्रतिवादी संख्या 3 ने सीजीआरएफ से संपर्क किया और उसके बाद, विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील दायर की। आदेश का अंतिम भाग, जिसके विरुद्ध निगम व्यथित है और वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय में प्रार्थना की है कि आदेश के इस भाग को रद्द कर दिया जाए, इस प्रकार है :---

"इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने लाइसेंसधारी को 10 दिसंबर 2003 से बैंक दर पर सुरक्षा जमा पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। बैंक दर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:--

"वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर स्वयं द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय बैंकों को धन उधार देता है"।

अप्रैल, 2003 से 30 अगस्त 2007 तक प्रभावी बैंक दर 6% है। इसलिए, मैं लाइसेंसधारी डीएचबीवीएनएल को 10 दिसंबर, 2003 से 31 मार्च,2007 तक उपभोग सिक्यरिटी और मीटर सिक्यरिटी पर 6% की बैंक दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देता हूं। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए, बचत बैंक दर 3.5% की दर से, ब्याज का भुगतान 6% की दर से किया जाना चाहिए। अप्रैल, 2006 से 26 जुलाई, 2006 तक भी 6% प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। 10 दिसंबर 2003 से 31 मार्च,2007 तक ब्याज की रकम, यदि पहले से ही भुगतान नहीं किया गया है तो जनवरी, 2008 के महीने से आवेदक के वर्तमान बिलों में जमा किया जाना चाहिए और चालू वित्तीय वर्ष i.e 2007-08 के लिए ब्याज का भुगतान 6% प्रति वर्ष की दर से अप्रैल 2008 में किया जा सकता है।

दोनों पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करें।

फ़ाइल को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जा सकता है।"

(28) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री विकास सूरी का कहना है कि न केवल इस आदेश को ख़ारिज किया जाए, बल्कि इसे रद्द भी किया जाए क्योंकि लोकपाल के पास उपरोक्त आदेश सुनाने का कोई अधिकार और क्षेत्राधिकार नहीं था। याचिकाकर्ता निगम ने इस आदेश के खिलाफ एचईआरसी में अपील दायर की थी। इसे अनुबंध पी10 के माध्यम से वापस कर दिया गया था और आयोग द्वारा यह कहा गया था कि विद्युत लोकपाल के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(29) उपरोक्त तथ्य रिट याचिका में की गई दलीलों से एकत्र किए गए हैं।

(30) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिट याचिका पर दायर की गई प्रतिक्रिया में, कुछ भी ठोस बात सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि रिट याचिका में की गई दलीलों को खारिज कर दिया गया है और एक दलील दी गई है कि विद्युत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, लोकपाल के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता ने लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था।

(31) अब निर्णय के पहले भाग में तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है।

दोबारा : प्रश्न क्रमांक 1

(32) श्री सूरी ने बहुत जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षिप्त में "सीजीआरएफ") और बिजली लोकपाल को ब्याज दर तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह शक्ति केवल एचईआरसी में निहित है और अनुबंध पी8 के तहत एचईआरसी द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। विद्युत लोकपाल यह नहीं कह सकता कि प्रतिवादी संख्या 3 को 6% की दर से और पूर्वव्यापी रूप से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

(33) 2003 अधिनियम की धारा 47(4) वितरण लाइसेंसधारी को एचईआरसी द्वारा निर्दिष्ट बैंक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है। वर्तमान मामले में, मैन्युफ़ैक्चर एसोसिएशन, फ़रीदाबाद द्वारा दायर रिट याचिका में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा संदर्भित एक विवाद पर, एचईआरसी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और यह निर्धारित किया कि आदेश (अनुलग्नक पी8) के माध्यम से सिक्यरिटी जमा पर कितना ब्याज दिया जाना है। एचईआरसी ने 2003 अधिनियम की धारा 47(4), 2005 विनियमों के विनियम 5.7 को ध्यान में रखते हुए ब्याज निर्धारित करने की कवायद की और निष्कर्ष निकाला कि उपभोक्ता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैंक दर पर ब्याज का हकदार है। दूसरे शब्दों में, आयोग इस तथ्य से अवगत है कि 2005 विनियमन के विनियमन 5.7 में यह निर्धारित किया गया है कि एक उपभोक्ता ब्याज का हकदार है जो भारतीय स्टेट

बैंक के बचत बैंक खाता धारक को भुगतान किया जाता है और आयोग द्वारा यह कहा गया कि उपभोक्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर के अनुसार भुगतान किया जाना है। दूसरे शब्दों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय बैंक दरें भारतीय स्टेट बैंक के बचत बैंक खाताधारक को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर से अधिक या कम हो सकती हैं। इसलिए, ब्याज की किस दर का भुगतान किया जाना है यह एचईआरसी द्वारा निर्धारित किया गया था जो 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत उनके कार्यक्षेत्र में था। एचईआरसी ने ब्याज दर के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लिया। यह निर्धारित करने के बाद कि उपभोक्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय बैंक दर पर भुगतान किया जाना है, सीजीआरएफ और विद्युत लोकपाल को केवल यह समझना था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय बैंक दर क्या थी। इसलिए, यह विद्युत लोकपाल की शक्तियों के अंतर्गत है और उसने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है। उन्होंने केवल आदेश(अनुलग्नक पी8) को प्रभावी बनाया था न कि आयोग द्वारा 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित ब्याज दर को कम करने या बढ़ाने का कोई प्रयास किया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आदेश (अनुलग्नक पी8) अंतिम रूप ले चुका था और याचिकाकर्ता-निगम ने उस पर आपत्ति नहीं जताई थी। निगम के पास आयोग के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार उपलब्ध था। उन्होंने यह अधिकार छोड़ दिया था। इसलिए, विद्युत लोकपाल को एचईआरसी द्वारा निर्धारित आदेश के अनुसार कार्य करना था। विद्युत नियम, 2005 (संक्षिप्त में "2005 नियम") के नियम 7 का उपनियम (3) का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

" 7(3) लोकपाल उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने से पहले ,अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या इस संबंध में उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए सामान्य आदेशों या निर्देशों के अनुरूप, उपभोक्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करेगा।"

(34) इसलिए, विद्युत लोकपाल वर्तमान मामले में उपयुक्त आयोग (एचइआरसी) द्वारा दिए गए सामान्य आदेशों या निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कर रहा था। एचईआरसी ने अपने विवेक से 2004 विनियमन (अनुलग्नक पी1) के विनियम 23 को हटा दिया था। इस भाग को भी याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, अपील का जो अधिकार निहित था, उसे छोड़ दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है और यह निर्णित किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्युत लोकपाल आदेश (अनुलग्नक पी 9) पारित करने के अपने अधिकार में था क्योंकि यह उस आदेश(अनुलग्नक पी8) को प्रभावित करने के लिए था।

दोबारा: प्रश्न संख्या 2

(35) प्रश्न संख्या 2 को विस्तृत करते हुए श्री सूरी ने कहा है कि 2004 विनियमन के विनियम 2(m) और (n) के साथ पठित विनियम 2(h) के अनुसार विद्युत लोकपाल का प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर अपील से निपटना उसके अधिकारों से परे था।

(36) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि आदेश (अनुबंध पी 8) का कार्यान्वयन न करना न तो दोष है और न ही सेवा में कमी है, इसलिए, आदेश के निष्पादन के लिए बिजली लोकपाल से संपर्क नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने 2004 विनियमन के विनियम 2(m) और (n) पर निर्भरता दिखायी जो दोष और कमी को परिभाषित करता है। इन्हें फैसले के पहले हिस्से में पहले ही दोहराया जा चुका है। इस तर्क पर पूरी ताकत लगाते हुए, याचिकाकर्ता 2004 के विनियमन 2(h)(ii) से अनभिज्ञ हो गया था। एक उपभोक्ता हमेशा शिकायत में आग्रह कर सकता है कि जमा राशि को रोके रखना और क़ानून की आवश्यकता के अनुसार ब्याज का भुगतान न करना एक अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा है। ब्याज का भुगतान न करना एक अनुचित व्यवहार है, खासकर तब जब 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत लाइसेंस धारक पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व डाला गया है। इसलिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यह है कि विद्युत लोकपाल इस मामले से निपट सकता है क्योंकि आयोग द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान न करना अनुचित व्यवहार है। अन्यथा भी, उपभोक्ता होने के नाते प्रतिवादी संख्या 3, 2004 विनियम के विनियम 2(h) के तहत शिकायत दर्ज करने का हकदार था। विनियम 2(k) उपभोक्ता विवाद को परिभाषित करता है। उपभोक्ता विवाद की परिभाषा बहुत व्यापक व प्रचलित है और ब्याज का भुगतान न करना या एचईआरसी द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान न करना सुरक्षित रूप से उपभोक्ता विवाद कहा जा सकता है। इसलिए, विद्युत लोकपाल विवादित आदेश (अनुलग्नक पी9) पारित करने के अपने अधिकार क्षेत्र में था।

दोबारा : प्रश्न संख्या 3

(37) श्री सूरी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता-निगम 2003 से सिक्यरिटी जमा पर 2005 के विनियमों के तहत निर्धारित दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किए जा रहा था। श्री सूरी आगे कहते हैं कि 2005 के विनियमों के अनुसार, उपभोक्ता उस दर पर ब्याज का भुगतान करने का हकदार था जिस दर पर भारतीय स्टेट बैंक का बचत बैंक खाता धारक हकदार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2005 से उपभोक्ता को 3.5% की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था। ब्याज का भुगतान उस तारीख से किया गया था जब अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2005 (अनुलग्नक पी5) जारी की गई थी और 2005 विनियम अधिनियमित किए गए थे। श्री सूरी ने आगे प्रस्तुत किया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि एचईआरसी द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी8) के अनुपालन में, याचिकाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक

दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य था, जिसका भुगतान आदेश यानी 27 जुलाई, 2006 से किया जाना है, यह प्रस्तुत किया गया है कि लोकपाल ने यह आदेश देकर गंभीर त्रुटि की है कि प्रतिवादी संख्या 3, 10 दिसंबर, 2003 से 6% की दर से ब्याज का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि निर्देश आयोग द्वारा जारी आदेश (अनुलग्नक पी8) को संभावित रूप से लागू किया जा सकता है, न कि पूर्वव्यापी रूप से। वकील ने प्रार्थना की है कि आदेश का वह भाग, जिसके द्वारा उपभोक्ता को पूर्वव्यापी प्रभाव से ब्याज प्रदान किया गया, क्षेत्राधिकार न होने के कारण रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया विवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रह सकता कि उपभोक्ता ब्याज का भुगतान न करने पर आंदोलन कर रहे थे। मैन्युफ़ैक्चरर असोसीएशन, फ़रीदाबाद ने 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 2847 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था। इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया था। तदनुसार, आदेश (अनुलग्नक पी8) पारित किया गया और उपभोक्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर पर ब्याज का हकदार माना गया। एक बार उपयुक्त आयोग, एचईआरसी, द्वारा दर निर्धारित कर दिए जाने के बाद, लोकपाल केवल उसी पर प्रभाव डाल रहा था। अत: ब्याज दर निर्धारित करने के बाद उन्होंने अप्रैल, 2003 से उपभोक्ताओं को ब्याज का हकदार माना था। 2003 अधिनियम को 10 दिसंबर, 2003 को हरियाणा में लागू किया गया। 2003 अधिनियम की धारा 47(4) के तहत उपभोक्ता ब्याज के भुगतान के हकदार थे। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में उपभोक्ता उस तारीख से ब्याज के हकदार होंगे जब 2003 अधिनियम को हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया था, यानी 10 दिसंबर, 2003 से ना कि अप्रैल, 2003 से। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यह है कि लोकपाल आदेश (अनुलग्नक पी 8) को प्रभावी कर रहा था क्योंकि उपभोक्ता उसी दिन से ब्याज की मांग कर रहे थे जिस दिन वे इसके हकदार बन गए थे और रिट याचिका और बाद में एचईआरसी से संपर्क करके अपने दावों को आगे बढ़ाया था। लेकिन वैधानिक अधिकार उन्हें 10 दिसंबर, 2003 से मिला। इसलिए, उस तारीख से उपभोक्ता ब्याज के हकदार होंगे।

दोबारा: प्रश्न संख्या 4

(38) पार्टियों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 3 पर चर्चा करते समय, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है और किसी अलग चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

दोबारा: प्रश्न संख्या 5

(39) 2005 के नियमों के नियम 7(3) का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है कि लोकपाल उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों पर विचार करने के लिए बाध्य है। इसलिए, एचईआरसी द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी8) एक निर्देश था जिसे लोकपाल नजरअंदाज नहीं कर सकता था और उसे उसी पर अमल करना था। इसलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सकारात्मक है।

दोबारा: प्रश्न संख्या 6

(40) 2005 विनियमों के विनियम 5.7 पर विचार करने के बाद उपयुक्त आयोग एचईआरसी। ने निर्देश दिया कि उपभोक्ता सिक्यरिटी जमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैंक दर पर ब्याज भुगतान के हकदार हैं ।आदेश (अनुलग्नक पी9) में लोकपाल ने बैंक दर की निम्नलिखित परिभाषा पर ध्यान दिया है:

बैंक दर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय बैंकों को धन उधार देता है"।

(41) श्री सूरी ने बहस के दौरान बहुत निष्पक्षता से कहा है कि लोकपाल द्वारा दी गई बैंक दर की परिभाषा विवादित नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि बैंक दर के अनुसार प्रासंगिक समय पर यह दर 6% थी। यह निवेदन कि प्रासंगिक समय पर बैंक दर 6% थी और बैंक दर की परिभाषा, श्री सूरी द्वारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड,हिसार के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) लेखा अधिकारी, रमेश कामरा के निर्देश पर दी गई है।

(42) श्री चावला ने हालांकि कहा कि उपभोक्ता 6% से अधिक ब्याज दर के हकदार थे क्योंकि 1992 में जारी बिक्री परिपत्र में 10% ब्याज दर निर्धारित की गई थी, लेकिन वह भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरेट की परिभाषा को खारिज करने में विफल रहे हैं। वह यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज़ पेश करने में भी विफल रहे कि मौजूदा समय में, भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक दर 6% से अधिक थी। अन्यथा भी, वितरण लाइसेंसधारी-प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर की गई रिट याचिका में यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि ब्याज की उच्च दर प्रदान की जाए क्योंकि आदेश (अनुलग्नक पी 9) को स्वीकार कर लिया गया था और इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी। श्री चावला ने कहा है कि 6% ब्याज देना उपभोक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई।

(43) इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद कि उपभोक्ता दिसंबर, 2003 से ब्याज पाने का हकदार है, न कि अप्रैल, 2003 से, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

(44) यदि श्री विकास सूरी, अधिवक्ता द्वारा की गई कड़ी मेहनत को स्वीकार और मान्यता नहीं दी गई तो यह न्यायालय अपने कर्तव्य में असफल होगा। वास्तव में श्री सूरी ने पूरी वाकपटुता के साथ इस न्यायालय को निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत सावधानी से सहायता की है, भले ही वही बातें उनके खिलाफ गई हों।

(45) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।[1]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा

---

[1] आर.एन.आर